भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3039

27 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

घरेलू इस्पात उत्पादन

3039. श्री संदोष कुमार पी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू इस्पात का कितना उत्पादन हुआ है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों से आयात किए गए इस्पात की मात्रा कितनी है;
(ग) देश में घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है; और
(घ) इस्पात क्षेत्र के अंतर्गत "मेक इन इंडिया" पहलों में क्या प्रगति हुई है और इस्पात के आयात पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) और (ख): देश में विगत तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के दौरान क्रूड इस्पात के उत्पादन तथा तैयार इस्पात के आयात का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**क्रूड इस्पात उत्पादन (एमटी)**	**तैयार इस्पात का आयात (एमटी)**
2019-20	109.14	6.77
2020-21	103.54	4.75
2021-22	120.29	4.67
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन		

(ग) और (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है। उत्पादन, आयात, निर्यात जैसे निर्णय बाजार संचालित हैं तथा इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिए जाते हैं। सरकार ने देश में स्वदेशी इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत-सी पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मेड इन इंडिया इस्पात की खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का क्रियान्वयन। डीएमआई एंड एसपी नीति के

क्रियान्वयन की शुरुआत से अब तक कुल 34,808 करोड़ रुपये मूल्य की इस्पात खरीद की गई है।

ii. परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) की स्थापना, जो नए निवेशों को सुकर बनाने के लिए परियोजनाओं की पहचान, परियोजनाओं की चरणबद्धता का मूल्यांकन और इनके क्रियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है।

iii. देश में विशेष इस्पात के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

iv. दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्स्पो जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी, भारत में इस्पात क्षेत्र की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालयीन प्रतिनिधिमंडल की जापान, कोरिया, रूस में स्वदेशी इस्पात उपभोक्ताओं के साथ चर्चा तथा भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश के अवसरों के साथ-साथ व्यापारिक क्षमता को प्रदर्शित करना।

v. देश के इस्पात क्षेत्र में इस्पात उपयोग, इस्पात की समग्र माँग और निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित क्षमतावान उपभोक्ताओं को और अधिक शामिल करके मेक इन इंडिया पहल तथा प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

vi. भारतीय इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे कारोबारी सुधारात्मक उपायों के अंशांकन के साथ इस्पात उत्पादों तथा कच्चे माल पर आधारभूत सीमा शुल्क में समायोजन।

****